बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 19 ● नई दिल्ली ● शनिवार 25 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

विधानसभा सत्र आज से, पूर्ण राज्य के साथ ही जमीन और बिजली पर होगी बड़ी बहस

जम्मू । विधान-सभा का मानसून सत्र वीरवार से शुरू होगा। करीब छह माह बाद होने जा रहा यह सत्र सीमित जरूर रहेगा लेकिन इसमें बड़ी बहस सुनाई देगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सदन में एक विधायक अधिकतम दस सवाल पूछ सकेगा। 450 सवाल सदन में उठने वाले हैं। 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल और 55 प्रस्ताव भी विधानसभा को भेजे गए हैं। बीते छह माह में हुए तमाम बड़े घटनाक्रमों पर राजनीतिक दलों ने सदन में प्रस्ताव भेजकर चर्चा मांगी है। मंत्रिमंडल ने बीते दिनों पंचायती राज एक्ट 1989, शॉप एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बिल और गुड्स एंड सर्विसेज 2017 में बदलाव को मंजूरी दी है.

दिल्ली को अभी प्रदूषण से राहत नहीं, इस इलाके की सबसे ज्यादा हवा

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। शुक्रवार सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। यह स्थिति न केवल दिल्ली के निवासियों के लिए, बल्कि विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक है। आनंद विहार के अलावा, शहर के अन्य प्रमुख इलाकों में भी वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आईटीओ क्षेत्र में एक्यूआई 316 दर्ज किया गया। वहीं इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों में एक्यूआई 254, धौला कुआं में 257 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूर्वानुमान है कि सोमवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। इसके चलते सांस के मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या भी हो सकती है।

बृहस्पतिवार को अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 2650 मीटर रही। वेंटिलेशन इंडेक्स 14500 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। सीपीसीबी के अनुसार, बीते 24 घंटे में हवा की गति में इजाफा हुआ है। ऐसे में बृहस्पतिवार को हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग की मानें तो 27 अक्तूबर से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अब दिल्ली-एनसीआर पर इस पश्चिमी विक्षोभ का क्या असर होगा इस बारे में अपडेट नहीं मिल पाया है। हालांकि उससे पहले 26 अक्तूबर को दिल्ली में बेहद हल्के बादलों की मौजूदगी देखी जा सकती है। इस हफ्ते बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में उम्मीद 27 अक्तूबर से आने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ से है। वहीं अगर दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों की बात करें तो यहां पर वायु गुणवत्ता ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन राहत वाली भी नहीं है। आज शुक्रवार को गाजियाबाद के संजय नगर में 208, वहीं नोएडा सेक्टर एक में 170 और सेक्टर 125 में 175 एक्यूआई पहुंच गया है। नोएडा रेड से ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। बीते दिन प्रदूषण का एक्यूआई 300 से कम हुआ। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 180 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद का एक्यूआई सुबह 7 बजे 200 के करीब रहा। एनआईटी में 230, सेक्टर 30 में 166, बल्लभगढ़ में 109 एक्यूआई दर्ज किया गया है। फरीदाबाद क्षेत्र में स्थित सेक्टर - 11 और सेक्टर 16 ए की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन प्रदूषण का डेटा नहीं दिखा रही है।

ट्रायल हुआ पूरा: दिल्ली में कृत्रिम वर्षा की तारीख हुई

नई दिल्ली । दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए मौसमी दशा अनुकूल होने के चलते कृत्रिम बारिश का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में दीपावली के बाद हुई प्रदूषित हवा पर सरकार प्रहार करेगी।

इस मौके पर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके कारण इस अभिनव प्रयास के लिए सभी अनुमतियां समय पर उपलब्ध हो सकीं। सिरसा ने कहा कि गुरुवार को आईआईटी कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली क्षेत्र तक और वापस आईआईटी कानपुर तक एक ट्रायल सीडिंग उड़ान भरी गई, जिसमें खेकड़ा और बुराड़ी के बीच और बादली क्षेत्र में पायरो तकनीक का उपयोग करके क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स दागे गए।

यह उड़ान क्लाउड सीडिंग की क्षमताओं, विमान की तैयारी और क्षमता, क्लाउड सीडिंग फिटिंग और फ्लेयर्स की क्षमता का आकलन, और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की जांच के लिए एक परीक्षण उड़ान थी। राजधानी में

कृत्रिम बारिश करने को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को विशेषज्ञों की तरफ से बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया है। यही नहीं, मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्तूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो 29 अक्तूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। सीएम ने कहा कि यह पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का एक वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस नवाचार के माध्यम से राजधानी की हवा को स्वच्छ और वातावरण को संतुलित बनाया जा सके। इस प्रयास को सफल बनाने में लगे हमारे कैबिनेट सहयोगी पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड और नमक जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया जाएगा।

इसका उद्देश्य बादलों में संघनन बढ़ाकर बारिश कराना और हवा में मौजूद जहरीले कणों को नीचे गिराकर प्रदूषण कम करना है। विशेष सेना एयरक्राफ्ट कानपुर से मेरठ से पहुंच गया है, जो पाइरोटेक्निक तकनीक का उपयोग करेगा। एयरक्राफ्ट की दोनों विंग्स के नीचे 8 से 10 पॉकेट रखे गए हैं, जिनमें रासायनिक फ्लेयर्स रखी गई हैं। बटन दबाने पर ये फ्लेयर्स बादलों के नीचे ब्लास्ट होंगी, जिससे संघनन बढ़ेगा और बारिश होगी। इसका प्रभाव लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में महसूस किया जा सकेगा। कृत्रिम बारिश प्रदूषण में अस्थायी सुधार लाएगी। इस पहल से न केवल प्रदूषण कम करने की उम्मीद है, बल्कि यह विज्ञान और तकनीक के माध्यम से राजधानी में नई दिशा तय करने वाला कदम भी माना जा रहा है।

दुष्कर्म मामले में जमानत खारिजः दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- दोस्ती...दुष्कर्म का लाइसेंस नहीं

दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दोस्ती किसी आरोपी को पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे बेरहमी से पीटने का लाइसेंस नहीं देती। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पॉक्सो मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उसके इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि वह और शिकायतकर्ता दोस्त थे, इसलिए यह सहमति से संबंधित मामला हो सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता की ओर से यह दावा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोस्त थे और इसलिए यह सहमति से संबंधित मामला हो सकता है। इस अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले ही संबंधित पक्ष दोस्त थे, लेकिन दोस्ती याचिकाकर्ता को पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने, उसे अपने दोस्त के घर में कैद करने और बेरहमी से पीटने का कोई लाइसेंस नहीं देती।

मामले के अनुसार संगम विहार थाने में पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दोस्ती किसी आरोपी को पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे बेरहमी से पीटने का लाइसेंस नहीं देती। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पॉक्सो मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उसके इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि वह और शिकायतकर्ता दोस्त थे, इसलिए यह सहमति से संबंधित मामला हो सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता की ओर से यह दावा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोस्त थे और इसलिए यह सहमति से संबंधित मामला हो सकता है। इस अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले ही संबंधित पक्ष दोस्त थे, लेकिन दोस्ती याचिकाकर्ता को पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने, उसे अपने दोस्त के घर में कैद करने और बेरहमी से पीटने का कोई लाइसेंस नहीं देती। मामले के अनुसार संगम विहार थाने में पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 17 वर्षीय नाबालिग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह आरोपी को कई वर्षों से पड़ोसी के रूप में जानती थी। आरोपी ने उसे इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की, 26 जून 2025 को मिलने बुलाया और गोविंदपुरी में अपने दोस्त के घर ले जाकर पीटा और बार-बार दुष्कर्म किया। डर की वजह से उसने शुरू में घटना की रिपोर्ट नहीं की और मेडिकल जांच से भी इनकार कर दिया। पांच जुलाई 2025 को आरोपी की मां और उसकी मां के बीच झगड़े के बाद उसने अपनी मां को घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज हुई। एमएलसी रिपोर्ट में पीड़िता की बाईं आंख के नीचे चोट और दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जो आरोपों की प्रारंभिक पुष्टि करती है। अदालत ने कहा कि नाबालिग होने के कारण वह सदमे और शर्म की वजह से शुरू में कुछ नहीं बता सकी, और प्राथमिकी में देरी या तारीख में विसंगति का मुद्दा ट्रायल का विषय है। अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया और उसकी अग्रिम जमानत याचिका पहले चार बार खारिज या वापस ली जा चुकी है।

राजधानी में छाने लगी सूर्य उपासना के महापर्व छठ की छटा

दिल्ली । राजधानी के विभिन्न हिस्सों में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। कृत्रिम घाटों के साथ यमुना के प्राकृतिक घाटों पर भी श्रद्धालु अर्घ्य देंगे। इस पर्व के दौरान सांस्कृतिक विविधता और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। दिल्ली सरकार, स्थानीय प्रशासन और छठ पूजा समितियां घाटों को सजाने और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करने में जुट गई हैं। पांच साल बाद यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति मिलने से पूर्वांचल वासियों में विशेष उत्साह है। खास बात यह है कि इस बार आईटीओ के छठ घाट (हाथी घाट) को भव्य रूप से सजाया जा रहा है, जहां भोजपुरी गीतों की गूंज के बीच श्रद्धालु सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। आईटीओ छठ घाट को साफ-सुथरा करने और पूजा के लिए उपयुक्त बनाने का काम तेजी से चल रहा है। द्वारका स्थित अखंड युवा शक्ति छठ घाट समिति भी घाट की तैयारियों में लगी हुई है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के श्रद्धालु खाली प्लॉटों और पार्कों में अस्थायी छठ घाट बना रहे हैं। श्रद्धालुओं ने पार्कों में गड्ढे खोदकर उनको तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे छठ महापर्व के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर सकें। श्रद्धालुओं का कहना है कि यमुना में पूजा करने से प्रदूषण फैलने का खतरा रहता है, इसलिए वह इस बार पूजा स्थल अपने ही मोहल्ले या कॉलोनी में बनाएंगे, ताकि जल स्रोत स्वच्छ रहे। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, कड़कड़डूमा, मंडावली, दिलशाद गार्डन, गोकुलपुर, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क और करावल नगर जैसे इलाकों में लोग सामूहिक रूप से पार्कों को छठ पूजा के लिए तैयार कर रहे हैं। स्थानीय आरडब्ल्यूए और समाजसेवी संगठन के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन की मदद से घाटों पर सफाई और रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। दक्षिणी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। हरकेश नगर, वसंत कुंज, ग्रेटर कैलाश, नेहरू एनक्लेव, साकेत, सर्वोदय एनक्लेव, छतरपुर और घिटोरनी जैसे इलाकों में स्थित पार्कों में सफाई अभियान और घाट बनाने का कार्य शुरू हो गया है। स्थानीय आरडब्ल्यूए और निवासी मिलकर पार्कों की साफ-सफाई, कटाई-छंटाई और पूजा स्थल तैयार करने में जुटे हैं।

पटाखों से चार मंजिला इमारत में लगी आग से लाखों का नुकसान, पांच परिवारों का पूरा सामान

इंदिरापुरम । शक्तिखंड दो स्थित चार मंजिला इमारत में लगी आग की जद में पांच फ्लैट आए थे। आग की लपटों में यहां रहने वाले लोगों का लाखों का सामान जला दिया है। तीन दिन पहले सोसायटी में दिवाली की खुशियां थीं जो बृहस्पतिवार को सन्नाटे में बदल गया था। लोग अपनी जमा पूंजी के जल जाने से परेशान रहे। हालांकि इस दौरान सब एक दूसरे को दिलासा भी देते रहे। बृहस्पतिवार को अपार्टमेंट परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। लोग फ्लैट की बजाय परिसर में ही बैठे रहे और आग से हुए नुकसान पर एक दूसरे से चर्चा करते रहे। इस दौरान दोपहर दो बजे तक भी बहुत से लोगों ने संचित सामान जल जाने के दुख में खाना नहीं खाया था। अपार्टमेंट में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं ने लोगों को दिलासा दिया और खाने के लिए कहा। सबसे पहले आग की लपटें पहली मंजिल पर रहने वाले दीपक कुमार के फ्लैट में लगी थी। दीपक ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे कॉलोनी के कुछ लोग नीचे पटाखे फोड़ रहे थे। थोड़ी देर पहले ही उन्हें कॉलोनी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अशोक त्यागी ने पटाखे फोड़ने को मना किया था लेकिन वह नहीं माने और लगातार पटाखे फोड़ते रहे। बालकनी में कपड़े सूख रहे थे। नीचे से पटाखा उड़कर बालकनी में सूखे कपड़ों पर आकर गिर गया और आग लग गई। दीपक का कहना है कि वह वर्क फ्राम होम कर रहे हैं बाहर के कमरे में होते तो शायद आग का जल्दी उन्हें मालूम हो जाता लेकिन पटाखों की शोर की वजह से वह अंदर कमरे में थे। ऐसे में मालूम नहीं हो सका। आग की लपटें जब तक पता चली सामान बचाने की बजाय बच्चे और पत्नी के साथ तुरंत बाहर निकल आए। देर रात तक वह और अन्य लोग भी डर से कांप रहे थे और घर के अंदर नहीं गए। उन्होंने बताया कि आग में उनका पूरा फर्नीचर जल गया है।नीरज ने बताया कि लोगों के थोड़ से सुख ने पूरे जीवन की जमा पूंजी को नष्ट कर दिया है। मैं रात ऑफिस से घर लौटा ही था और कपड़े बदल रहा था। इसी दौरान आग लगने का शोर मचा और लोग घर से बाहर भागने लगे तो मैं भी परिवार के सदस्यों के साथ घर से बाहर निकल आया। अब घर के अंदर केवल दीवार बची हुई है।

सम्पादकीय...

मतांतरण रोधी कानून

राजस्थान सरकार ने छल-बल या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले मत परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जो 'धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक' पारित किया था, वह राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बन गया है। इस अधिनियम में जबरन या कपटपूर्ण मतांतरण के विरुद्ध अत्यंत कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के अनुसार, मतांतरण से जुड़े सभी अपराध गैर-जमानती होंगे, जिनकी सुनवाई सत्र न्यायालय में की जाएगी और आरोपितों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। मतांतरण का प्रश्न केवल आस्था या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज की एकता, सांस्कृतिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से छल-बल, प्रलोभन या लालच के माध्यम से मतांतरण कराने के अनेक मामले सामने आए हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र में इस प्रकार की गतिविधियां न केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौती बनी हुई है, बल्कि ये सामाजिक समरसता को भी कमजोर कर रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में राजस्थान सरकार ने यह कानून बनाकर संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का जबरन या कपटपूर्ण मत परिवर्तन न तो व्यक्तिगत अधिकारों के नाम पर स्वीकार्य होगा और न ही समाज के हित में सहनीय। भारत में मतांतरण सदियों से पोषित, संगठित, सुनियोजित वैश्विक अभियान का हिस्सा है। इस्लाम और ईसाइयत द्वारा संचालित मतांतरण की प्रक्रिया ने भारत की सनातन संस्कृति और दर्शन को उसकी उदारता, सहिष्णुता और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के कारण हमेशा से निशाने पर रखा है। आज देश का शायद ही कोई राज्य ऐसा हो, जहां मतांतरण के कपटपूर्ण धंधे को संगठित रूप से न चलाया जा रहा हो। मतांतरण में लिप्त लोग दलित, वंचित और भोले-भाले निर्धन समुदायों को अपना शिकार बनाते हैं। जब प्रलोभन से बात नहीं बनती, तो वे छल, कपट, झूठे चमत्कार और मिथ्या धार्मिक एवं जातिवादी विमर्श का सहारा लेते हैं। कोई सेवा और चिकित्सा के नाम पर यह धंधा करता है, तो कोई जन्नत-दोजख के बहाने। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि देश के कई क्षेत्रों में मतांतरण ने स्थानीय जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। संपन्न माना जाने वाला पंजाब भी पिछले कुछ समय से मतांतरण कराने वाले पादरियों की सक्रियता का शिकार है। देश के लगभग दस राज्यों ने मतांतरण रोधी कानून बना रखे हैं। इनमें से कुछ राज्यों ने राजस्थान की तरह अपने मतांतरण रोधी कानून को कठोर भी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, लेकिन इसके बाद भी मतांतरण की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। बीते दिनों ही बरेली से खबर आई कि सुमित मैसी नामक पादरी को उसके साथियों समेत मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये लोग सामाजिक रूप से कमजोर तबके को निशाना बना रहे थे। इसके पहले खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मतांतरण रोधी कानून की कुछ धाराओं के बारे में कहा कि वे संविधान की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट चार राज्यों के मतांतरण रोधी कानूनों पर उनसे जवाब मांग चुका है। स्पष्ट है कि मतांतरण रोधी कानूनों को कठोर करने की अपनी सीमाएं हैं। यदि हम मतांतरण रोधी कानूनों के प्रभाव का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि कानून तो बना दिए जाते हैं और उन्हें कठोर भी कर दिया जाता है, पर उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। मतांतरण में लिप्त लोग समाज के जिन वर्गों को अपना शिकार बनाते है, उनमें उतनी जागरूकता नहीं होती कि वे इन तत्वों के विरुद्ध समय पर समुचित कानूनी कार्रवाई कर सकें या उनकी तिकड़मों को समय रहते भांप सकें। आखिर कठोर कानून होने के बावजूद मतांतरण के अपराध में संलिप्त सजा पाने वाले आरोपितों की संख्या लगभग नगण्य क्यों है? मतांतरण पर लगाम न लग पाने का एक कारण सामाजिक भी है। आज भी हिंदू समाज जातियों के नाम पर बंटा है। यदि सामाजिक समरसता के भाव को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रबल नहीं किया गया तो विभाजनकारी शक्तियां समाज को बांटने के उद्देश्य में सफल होती रहेंगी। अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए लालायित राजनीतिक दल कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं। वे जातीय भेदभाव की आग में घी डालते हैं और कई बार मतांतरण रोधी कानूनों की आलोचना करते हैं। मतांतरण रोकने के लिए समाज के भीतर से ही एकता और समरसता की भावना एवं सांस्कृतिक चेतना का संचार होना चाहिए।

केवल विचारों के स्तर पर ही नहीं, जमीन पर भी सेवा, सहयोग, शिक्षा एवं चिकित्सा के सहस्रों प्रकल्प तथा संकल्प साकार होने चाहिए। मतांतरण केवल आस्था, उपासना एवं पूजा पद्धति आदि का ही रूपांतरण नहीं है। वह राष्ट्रांतरण भी है। जब तक यह बोध समाज के प्रत्येक वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मतांतरण रोधी कानून पूरी तरह सफल नहीं हो सकेंगे, भले ही उन्हें कितना कठोर क्यों न किया जाता रहे। मतांतरण रोधी कानूनों को कठोर बनाने के साथ इसके लिए भी प्रयत्न होने चाहिए कि किसी का भी छल-कपट से मतांतरण होने ही न पाए। ये प्रयत्न सरकार के प्रत्येक अंग के साथ समाज को भी करने होंगे।

डॉ. शमा मोहम्मद: भारत में खिलाड़ियों का प्रदर्शन मायने रखता है, सरनेम नहीं

विनोद पाठक

जब खिलाड़ी मैदान पर उतरते है तो उनका धर्म नहीं, बल्कि प्रदर्शन की कसौटी मायने रखती है। विडंबना यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने क्रिकेट टीम के चयन में सांप्रदायिकता और धर्म को ढूंढने की कोशिश की है। उन्होंने इंडिया-ए टीम के सिलेक्शन को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सरफराज खान को उनका सरनेम होने की वजह से टीम से बाहर रखा गया? डॉ. शमा मोहम्मद के बयान ने न केवल क्रिकेट, बल्कि राजनीति और समाज की परतों में नई हलचल पैदा कर दी। बेहतर तो यह होता कि कांग्रेस प्रवक्ता सवाल उठाने से पहले थोड़ा सोचकर स्वयं जवाब ढूंढतीं। बेहतर होता वो देश की सबसे पुरानी पार्टी को खेलों में राजनीति से दूर रखतीं। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) एक स्वायत्त संस्था है, जो किसी राजनीतिक दल के अधीन नहीं है। वर्तमान चयन समिति में पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर (मुख्य चयनकर्ता), एस.एस. दास, अजय रात्रा, सुब्रोतो बनर्जी और श्रीधरन शरथ शामिल हैं। इन सभी को उनके खेल अनुभव, योगदान और तकनीकी समझ के आधार पर चुना गया है। चयन का आधार केवल रन, विकेट, फिटनेस और टीम बैलेंस है। धर्म, जाति या नाम जैसे तत्वों की भूमिका नहीं होती। भारत के क्रिकेट इतिहास में मुश्ताक अली, अब्बास अली बेग, सैयद किरमानी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, वसीम जाफर, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे नाम बताते है कि मुस्लिम खिलाड़ियों ने हमेशा टीम इंडिया की प्रतिष्ठा को ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने खेल को राष्ट्र निर्माण का साधन मानते हुए 'खेलो इंडिया', 'टारगेट ओलंपिक पोडियम' जैसी योजनाओं की शुरुआत की। सरकार का जोर प्रतिभा आधारित चयन और खेल संरचना के विस्तार पर रहा है। इन योजनाओं में मुस्लिम खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर किसी स्तर पर कोई आधिकारिक भेदभाव का प्रमाण नहीं है। वर्ष 2021 में जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच में मोहम्मद शमी को सोशल

मीडिया पर ट्रोल किया गया था, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनका मनोबल बढ़ाया था। यह उदाहरण बताता है कि सरकार ने कभी भी धर्म आधारित विभाजन को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि एकता और समर्थन का संदेश दिया। डॉ. शमा मोहम्मद के आरोप को केवल सांप्रदायिक बयान कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। उनका सवाल एक सामाजिक सोच की झलक है कि क्या भारत का माहौल, खासकर सोशल मीडिया की विभाजनकारी प्रवृत्तियां, खेल जैसे निष्पक्ष क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही हैं? यह सवाल वाजिब है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी को उसकी हार या प्रदर्शन के बाद धर्म के नाम पर ट्रोल किया जाता है तो यह सामाजिक विकृति का संकेत है, लेकिन यह भी सच है कि टीम चयन में धर्म का प्रभाव नहीं, बल्कि जनता की प्रतिक्रियाओं में सामाजिक ध्रुवीकरण दिखता है। यह फर्क समझना जरूरी है। सरकार या बीसीसीआई नहीं, बल्कि समाज की कुछ आवाजें खेल को धर्म के चश्मे से देखने लगी है। वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दो प्रमुख मुस्लिम खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। घरेलू क्रिकेट में सरफराज खान, राशिद दर, मोहम्मद मोहसिन, सलमान नजीर जैसे युवा लगातार प्रदर्शन से चयन की कतार में हैं। महिला क्रिकेट में सैयदा खदीजा, इशरत फातिमा जैसी युवा खिलाड़ी घरेलू सर्किट में अपना नाम बना रही हैं।

क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी मुस्लिम खिलाड़ियों का योगदान भारत के खेल इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा है। हॉकी में जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद, सैयद मुश्ताक अली जैसे नाम भारत की खेल विरासत का गौरव हैं। वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मोहम्मद ईद, अब्दुल रहमान, सैयद अनवर जैसी नई प्रतिभाएं उभर रही हैं। महिला हॉकी में भी नाजिया खान, सायरा बेग जैसी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना रही हैं। फुटबॉल में मोहम्मद राशिद, फैय्याज अहमद, मोहम्मद रफी जैसे खिलाड़ी इंडियन सुपर लीग में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल ब्लास्टर्स और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जैसे ऐतिहासिक क्लबों ने दशकों से मुस्लिम खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। कुश्ती में नसीर अहमद और रहीम खान जैसे पहलवानों ने अपने संघर्ष और समर्पण से पहचान बनाई है, जबकि हाल में एशियन गेम्स में अब्दुल रहमान ने ग्रीको-रोमन वर्ग में पदक जीतकर नई उम्मीद जगाई। बॉक्सिंग में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतकर यह सिद्ध किया कि मुस्लिम युवा भी ओलंपिक और विश्वस्तरीय मुकाबलों में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। टेनिस में सानिया मिर्जा भारतीय खेल इतिहास की प्रेरक शख्सियत हैं। उन्होंने न केवल ग्रैंड स्लैम जीतकर देश का नाम ऊंचा किया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक भारतीय मुस्लिम महिला खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर कैसे चमक सकती है?

सानिया के बाद अब नई पीढ़ी में कश्मीरी खिलाड़ी सारा इनाम, हैदराबाद की अलीना सैयद जैसे नाम उभर रहे हैं। बैडमिंटन में सैयद मोहम्मद इरफान, अनीसा शेख जैसे युवा खिलाड़ी खेलो इंडिया और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। शूटिंग में मेहरान खान, अर्शद हुसैन जैसे निशानेबाज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय झंडा ऊंचा कर रहे हैं। एथलेटिक्स में नुजहत परवीन, निशानेबाजी में हीना सिद्दीकी और कबड्डी में सायमा अंसारी जैसी खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि भारत की मुस्लिम बेटियां खेलों में किसी से पीछे नहीं हैं। वे न केवल खेल रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी दे रही हैं। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तब पूरी टीम उन्हें अज्जू भाई कहकर सम्मान देती थी। जब मोहम्मद शमी ने विश्वकप में हैट्रिक ली तो पूरा देश एक साथ उनकी जीत पर गर्व कर रहा था। जब हॉकी के जफर इकबाल ओलंपिक मैदान पर तिरंगे के साथ दौड़े, तब किसी ने यह नहीं पूछा कि उनका धर्म क्या है? जब सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉफी उठाई तो भारत के हर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। यही वह भारत है, जो अपने खिलाड़ियों को केवल उनकी मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा के लिए याद रखता है, न कि उनकी पहचान के लिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने डॉ. शमा मोहम्मद को सटीक जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चयनकर्ताओं और कोच के पास हमेशा एक योजना होती है। कभी-कभी प्रशंसकों की नजर में वह गलत लग सकती है, लेकिन कृपया बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश न करें या ऐसी कहानियां न बनाएं, जो सच्चाई के करीब न हों। भारतीय खेलों की असली खूबसूरती यही है कि यहां धर्म नहीं, प्रदर्शन गिना जाता है। जहां विकेट, गोल, पंच और रिकॉर्ड ही पहचान बनते हैं। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे खेल के मैदान को सामाजिक एकता का प्रतीक बनने दें, न कि उसे सियासी बहस का शिकार बनाएं। जब तक भारत का खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहा रहा है, तब तक यह देश सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर केवल एक ही बात कहता रहेगा, खेल ही हमारी असली पहचान है।

क्या मध्यप्रदेश में भी लागू होगा 'गुजरात फॉर्मूला'?

सुरेश तिवारी

मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों यह आम चर्चा है कि क्या मध्यप्रदेश में भी 'गुजरात फॉर्मूला' लागू होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लगातार हो रहे दिल्ली दौरे को इससे जोड़ा जा रहा है, जहां वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हर बार मिलते हैं। पता चला है कि पार्टी हाई कमान भी मध्य प्रदेश में गुजरात पैटर्न पर बदलाव करने के पक्ष में है। बिहार चुनाव के बाद कभी भी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि इस तरह के बदलाव से सरकार में नई ऊर्जा आएगी और जनता के बीच बेहतर संदेश जाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसे कई मंत्री जो या तो बड़बोले माने जाते हैं या जिनका प्रदर्शन ठीक नहीं है, उन्हें हटाया जा सकता है। पार्टी संगठन ने ऐसे मंत्रियों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। मध्य प्रदेश के कभी मुख्य सचिव रहे गोपाल रेड्डी के बेटे अंशुमन के विवाह का रिसेप्शन आगामी 9 नवंबर को हैदराबाद में होगा। जानकारी के अनुसार जिस परिवार से उनके बेटे की शादी हो रही है उसका संबंध तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से है। बताया गया है कि रेवंत रेड्डी के बड़े भाई की बेटी रचना अब गोपाल रेड्डी की बहू होंगी।

बता दें कि गोपाल रेड्डी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल के आखिरी 9 दिनों यानी 16 मार्च से 24 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। लेकिन, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, इकबाल सिंह बैंस फिर से मुख्य सचिव बन गए थे। मध्य प्रदेश में आबकारी अधिकारियों के पिछले कुछ महीनों से अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। 2003 के शराब ठेका फर्जीवाड़ा मामले में आबकारी विभाग के सेवानिवृत्त उपायुक्त विनोद रघुवंशी को भोपाल की शाहपुरा पुलिस ने गत दिनों गिरफ्तार किया गया। भोपाल जिला कोर्ट ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी। राज्य शासन ने प्रभारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता रीवा आलोक खरे को पिछले सप्ताह सस्पेंड कर दिया गया। लोकायुक्त पुलिस द्वारा खरे के विरुद्ध की गई छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। लोकायुक्त पुलिस ने आबकारी विभाग द्वारा दी गई अभियोजन की स्वीकृति के बाद इसी माह खरे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। इसके चलते शासन ने यह कार्रवाई की है। अलीराजपुर से इसी साल अगस्त में सेवानिवृत्त हुए आबकारी अधिकारी भदौरिया के इंदौर-ग्वालियर के ठिकानों पर मारे गए छापे के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक के नकद मिले हैं। इसके अलावा डेढ़ किलो सोने के बिस्किट, एक किलो सोने के आभूषण, दो किलो चांदी भी लोकायुक्त की टीम ने बरामद की है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

इंदौर के दो सहायक आबकारी अधिकारियों राजीव द्विवेदी और सुखनंदन पाठक से इंदौर के फर्जी चालान घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार में एक ऐसे प्रमुख अभियंता की संविदा नियुक्ति में वृद्धि कर दी है, जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में जांच लंबित है। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम में संविदा पर चल रहे प्रमुख अभियंता अनिल श्रीवास्तव की सेवा अवधि में फिर वृद्धि कर दी गई है। इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि तकनीकी कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण और सुचारू संचालन हेतु प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से प्रमुख अभियंता मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के पद पर नवीन नियुक्ति होने तक अस्थाई रूप से अनिल श्रीवास्तव की संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जाती है। श्रीवास्तव को सेवानिवृत्ति के बाद पिछले 2 साल से प्रमुख अभियंता के रूप में लगातार संविदा नियुक्ति दी जाती रही है। अब लगातार तीसरे साल फिर से संविदा नियुक्ति में वृद्धि करने से विभाग में यह चर्चा होने लगी है कि क्या अब विभाग में कोई योग्य इंजीनियर नहीं बचा है, जिसे इस पद पर बिठाया जा सके।

गठबंधन राजनीति का धर्म

आखिरकार बिहार में विपक्षी दलों के मोर्चे महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया। यह घोषणा कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की ओर से की गई। इसी के साथ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआइपी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया। अशोक गहलोत की इस घोषणा से पता चलता है कि अभी तक ऐसा नहीं हो सका तो कांग्रेस की अनिच्छा के कारण। इस अनिच्छा से यही झलका कि कांग्रेस को अभी गठबंधन राजनीति के धर्म का मर्म जानना है। आखिर वह यह साधारण सी बात क्यों नहीं समझ सकी कि बिहार में राजद ही मुख्य विपक्षी दल है और तेजस्वी यादव उसके सर्वमान्य नेता। कांग्रेस की मानें तो उसने महागठबंधन की एकजुटता के लिए यह घोषणा की। इसका मतलब है कि इस घोषणा में देर करके उसने अभी तक अपने ही गठबंधन की एकजुटता को कमजोर करने और समर्थकों के बीच संशय फैलाने का काम किया। क्या यह अच्छा नहीं होता कि वह पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप पेश करने पर सहमत हो जाती और वह भी तब, जब इसकी मांग हो रही थी? क्या कांग्रेस ऐसा कुछ मानकर चल रही थी कि महागठबंधन के जीतने की सूरत में तेजस्वी यादव के अतिरिक्त अन्य कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है? उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह बिहार में अपनी राजनीतिक महत्ता बनाए रखने के लिए राजद पर ही निर्भर है। उसकी ऐसी ही निर्भरता अन्य राज्यों में भी वहां के क्षेत्रीय दलों पर है। जब तक वह अपने बलबूते चुनाव लड़ने की सामर्थ्य नहीं जुटा लेती, तब तक उसे उन्हें दबाव में लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव को सीएम पद का प्रत्याशी घोषित करने के साथ-साथ वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी को जिस तरह डिप्टी सीएम के रूप में आगे लाया गया, उससे उनकी राजनीतिक हैसियत का अनुमान लगता है, लेकिन उनकी पार्टी तो महज 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

और कांग्रेस उससे चार गुने से अधिक सीटों पर। हालांकि अशोक गहलोत ने यह कहा कि और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, पर इससे यह संदेश ओझल नहीं होता कि कांग्रेस की राजनीतिक ताकत वीआइपी से भी कम है। निःसंदेह अशोक गहलोत की घोषणा से महागठबंधन और विशेष रूप से उसका नेतृत्व कर रहे राजद को लाभ मिल सकता है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि अब इस गठबंधन में सब कुछ सही हो गया है। महागठबंधन के 10 से अधिक प्रत्याशी एक-दूसरे के सामने हैं। इस विचित्र स्थिति को मैत्री मुकाबला कहा जा रहा है। आखिर यह मैत्री मुकाबला क्या होता है? ऐसे मुकाबले से यही रेखांकित होता है कि महागठबंधन के घटकों में आपसी तालमेल और विश्वास की कमी है। यह स्वाभाविक है कि भाजपा-जदयू इस कमी को तूल देंगे।

राहुल गांधी की नाकाम राजनीति, साख और कांग्रेस का समर्थन दरक रहा

सुरेंद्र किशोर

पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त, 2011 को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश की तरक्की में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन इससे निपटने के लिए उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। मनमोहन सरकार में भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक बड़े मामले सामने आए थे। इनमें 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में घोटाले के मामले सुर्खियों में छाए रहे। इस पर जब उनसे सवाल किया जाता तो वह कहते कि गठबंधन सरकारों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। केंद्र में जब उनकी सरकार बदली तो भ्रष्टाचार से निपटने का रवैया भी पूरी तरह बदल गया, बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भ्रष्टाचार पर उनका लचर रवैया भी केंद्र में सत्ता परिवर्तन का एक कारण बना। नरेन्द्र मोदी ने देश की कमान संभालने के पहले ही कह दिया था कि 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा।' मोदी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने इस संकल्प को बार-बार दोहराया भी। उन्होंने 2016 में कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और मैं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा कर ही दम लूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह कथित राजनीतिक विवशता का रोना न रोते हुए मोदी देश में नई प्रशासनिक संस्कृति की नींव डाल रहे हैं। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से परेशान कांग्रेस समेत एक दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि केंद्र सरकार सीबीआइ, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सवाल है कि यदि दुरुपयोग हो रहा है तो अदालतें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के कोई समझौता न करने वाले रवैये के कारण ही नेहरू-गांधी परिवार को यह अहसास हुआ है कि उन्हें ऐसे मामलों में कोई राहत नहीं मिलने वाली। ध्यान रहे कि नेशनल हेराल्ड से संबंधित मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका के आधार पर मनमोहन सिंह के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। नेहरू-गांधी परिवार ने शायद सोचा होगा कि मोदी सरकार में उन्हें इस मामले में रियायत मिल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों इस केस में जमानत पर हैं। उनका सत्ता में लौटने का सपना भी दूर-दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा। इस निराशा से उपजी कुंठा के कारण ही राहुल गांधी का अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं रह गया है। उन्होंने सत्य और असत्य का भेद मिटा दिया है। वे मोदी के खिलाफ धमकी, गाली-गलौज और अत्यंत अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। इसके चलते उन्हें कई मुकदमों का भी सामना करना पड़

रहा है, लेकिन लगता है कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके ऐसे रवैये से राजनीतिक विमर्श का स्तर रसातल में ही क्यों न चला जाए या संसद की गरिमा तार-तार हो जाए। अपने बड़बोलेपन में उन्हें यह भी अहसास नहीं रहता कि वे क्या कह रहे हैं। कभी वे भारतीय राज्य पर सवाल उठाते है कि भारत राष्ट्र न होकर महज राज्यों का एक संघ है तो कभी कहते है कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा-आरएसएस से ही नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्यव्यवस्था से है। इसी से राहुल गांधी की मानसिकता को समझा जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाए। जब आयोग ने राहुल से कहा कि वे अपने आरोपों के पक्ष में शपथपत्र दें तो राहुल उसके लिए राजी नहीं हुए। इसी से संकेत मिला कि उनके आरोपों में कितना दम था। महात्मा गांधी ने एक समय 'सत्य के साथ प्रयोग' किए थे, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी ने असत्य को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। जब उनके आरोप नहीं टिकते तो वे तुरंत नया राग छेड़ने लगते हैं। जब आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर निशाना साधने से बात नहीं बनी तो वे कहने लगे कि जदयू-भाजपा की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ऐसा आरोप मढ़ते हुए राहुल भूल गए कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के कुख्यात जंगलराज का हिस्सा उनकी पार्टी कांग्रेस भी रही है। लालू सरकार में बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय आठ हजार रुपये थी, वह नीतीश राज में बढ़कर 68 हजार रुपये हो गई है। वस्तुतः कुछ भी कह देना और उसके पक्ष में कोई साक्ष्य न देना राहुल गांधी की शैली बन गई है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने श्रीनगर में कहा था कि 'देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। उनका यौन शोषण हो रहा है, लेकिन पुलिस उन्हें न्याय नहीं दिला पा रही है।' इन आरोपों के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस राहुल गांधी के आवास पर तीन बार गई, मगर वे कोई ठोस जवाब और साक्ष्य नहीं दे सके। नीतिगत मामलों पर भी राहुल गांधी अपरिपक्वता का परिचय देते रहते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बदरा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, [illegible] दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

डिप्टी सीएम पहुंचे हमीदिया अस्पताल, कार्बाइन गन से घायलों का जाना हाल कहा-दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल । कार्बाइन गन से हुए हादसे में घायल युवाओं और बच्चों का हालचाल जानने उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल शुक्रवार को सुबह हमीदिया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली और सभी को उच्चस्तरीय इलाज और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टरों ने बताया कि हादसे में घायल हुए कुल 37 मरीजों में से 32 पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 5 मरीजों का इलाज जारी है। उप मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि राज्य सरकार उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ तक हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। शुक्ल ने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि सभी घायलों को सर्वोत्तम उपचार मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे की जांच जारी है और अवैध रूप से पटाखा या विस्फोटक सामग्री रखने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता सिंह, अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन तथा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे।

कार्बाइड गन के खतरे को लेकर दो साल पहले 2023 में ICMR भोपाल ने चेतावनी दी थी। ICMR के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बताया था कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रासायनिक प्रतिक्रिया से बनने वाली गैस 'एसिटिलीन' केवल धमाका नहीं करती, बल्कि आंखों की रोशनी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। यह स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेलमोलॉजी में प्रकाशित भी हुई थी। उसके बावजूद समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए।

जिसकी वजह से अब तक भोपाल के अलग-अलग अस्पतालों में लगभग 162 लोग कार्बाइड गन से घायल हो चुके हैं। इनमें अधिकांश की आंखें जल चुकी हैं और उन्हें देखने में परेशानी हो रही है।

एलएबी और केडीए के प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय के अधिकारियों संग हुई बैठक, तल्खी गायब

जम्मू । चार महीने के इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार को लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लद्दाख के मुद्दों पर बुधवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में शामिल लद्दाख के प्रतिनिधियों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता में कहीं कोई तल्खी नजर नहीं आई। गृह मंत्रालय ने मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। कर्तव्य भवन-3 में आयोजित यह बैठक लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख के नेतृत्व और गृह मंत्रालय (एमएचए) के बीच पहली औपचारिक वार्ता है। हाई पावर कमेटी की इस बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ ही संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की पुरानी मांग उठाई। उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज किए जाने के साथ ही लेह हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग रखी। बैठक में शामिल नेताओं ने बताया कि पिछली बैठकों के विपरीत गृह मंत्रालय के अधिकारियों का रुख सकारात्मक दिखा।

उन्होंने उनकी मांगों पर उच्चस्तर पर कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। जल्द ही एक और बैठक बुलाए जाने पर सहमति बनी। बैठक में शामिल लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि केंद्र सरकार के नुमाइंदों के लहजे में लद्दाख के मुद्दों को लेकर गंभीरता झलकी है। हमने अपनी सभी मांगों को गृह मंत्रालय के सामने रखा है। उम्मीद है कि अगली बैठक में मांगों पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य होगा। सांसद ने कहा कि गृहमंत्रालय के अफसरों ने सभी मुद्दों पर बगैर किसी टालमटोल के सुनवाई का भरोसा दिया है। कहा कि एक ही बैठक में समाधान नहीं निकलेगा। बातचीत में समय लगता है। अगली बैठक की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग ने की। इसमें बौद्ध बहुल लेह और शिया बहुल कारगिल, दोनों क्षेत्रों के वरिष्ठ राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल थे। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने अपनी जमीन, संस्कृति और रोजगार के लिए संविधानिक गारंटी पर अपनी बातें रखीं। उनका कहना था कि वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने पर लद्दाख में इन सुरक्षा उपायों का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अनिर्णायक दौरों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बैठक के मिनट्स जारी करने के साथ समय सीमा तय करने और फैसले लागू करने पर जोर दिया। लद्दाख में आरक्षण को लागू किए जाने पर भी प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय के नुमाइंदों के साथ चर्चा हुई। कुछ माह पहले केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख के बेरोजगारों को रोजगार के लिए डोमिसाइल नीति घोषित की गई थी, जिसमें उन्हें आरक्षण की घोषणा की गई थी।

वोट मांगने गए जदयू विधायक कौशल किशोर का जमकर हुआ विरोध, लोगों ने लगाए वापस जाओ के

नालंदा । नालंदा जिले में पहले चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रत्याशी और उनके समर्थक घर-घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन गुरुवार को नालंदा की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरे जिले में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर दो विडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वोट मांगने गए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को आम जनता ने जमकर खरी-खोटी सुनाई। राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक कौशल किशोर को गुरुवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब विधायक कौशल किशोर अपने समर्थकों के साथ राजगीर विधानसभा क्षेत्र के पोखरपुर गांव पहुंचे और लोगों से वोट की अपील करने लगे, तो ग्रामीणों ने उनका जोरदार विरोध किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बुड़बक विधायक वापस जाओ जैसे नारे लगाकर विधायक और उनके कार्यकर्ताओं का विरोध जताया। कुछ ग्रामीणों ने तो व्यंग्यात्मक लहजे में समर्थकों को मुर्गा खाने जैसी बातें भी कहीं। हालांकि, विरोध करने वाले व्यक्ति ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक कौशल किशोर ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। विकास की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के कारण जनता में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि चुनावी दौर में जब प्रत्याशी वोट मांगने आए तो जनता ने अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया। दूसरी घटना नालंदा विधानसभा क्षेत्र की है, जहां जदयू विधान पार्षद (एमएलसी) रीना यादव के पति पूर्व एमएलसी राजू यादव जदयू प्रत्याशी श्रवण कुमार के लिए वोट मांगने निकले थे। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के प्रह्लाद नगर गांव में जैसे ही राजू यादव ने अपने समर्थकों के साथ श्रवण कुमार के पक्ष में वोट देने की अपील शुरू की, ग्रामीणों ने महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। गांव में मौजूद लोगों ने छोटे मुखिया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जदयू प्रत्याशी श्रवण कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों घटनाओं ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार नालंदा जिले में चुनावी समीकरण काफी जटिल हो सकते हैं। जनता के विरोध ने सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रत्याशियों के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सोशल मीडिया पर इन विडियो के वायरल होने से चर्चा और तेज हो गई है।

एएसआई संदीप लाठर सुसाइडः नई सीसीटीवी फुटेज आई सामने, स्कूटर पर खेत में अकेला गया था संदीप

रोहतक । एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में नई फुटेज सामने आई है। संदीप लाढ़ौत गांव में स्कूटर पर सवार होकर अकेला ही जाता दिखाई दे रहा है। फुटेज 14 अक्तूबर को 11 बजकर 43 मिनट की है। इससे साफ हो गया है कि संदीप लाठर आत्महत्या केस में घटना के समय कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। आज जुलाना में संदीप लाठर की श्रद्धांजलि सभा है। इसमें आसपास के ग्रामीणों के भारी संख्या में पहुंचने की संभावना है। इसके लिए जुलाना के कन्या स्कूल में टेंट लगाया गया है। साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर के ममेरे भाई संजय लाढ़ौत ने बताया कि डीएसपी दलीप सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने रोहतक से लेकर लाढ़ौत तक सीसीटीवी कैमरों की जांच की है। उसके कार्यालय में भी टीम आई थी। सीसीटीवी फुटेज में एएसआई संदीप लाठर अकेला ही दिखाई दे रहा है। फुटेज जांच टीम अपने साथ लेकर गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की अब तक की जांच व रवैये से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। कई खाप पंचायतों व समाज के लोगों ने उनसे संपर्क किया था। परिवार एएसआई संदीप लाठर की मौत पर राजनीति नहीं चाहता। किसी तरह की जातिगत बयानबाजी देने से सभी को मना कर दिया था।

परिवार नहीं चाहता कि प्रदेश में 2016 जैसा माहौल बने। बल्कि 36 बिरादरी के बीच आपसी भाईचारा और मजबूत हो। उन्होंने कहा है कि जैसे परिवार संदीप लाठर के जाने से आहत है, उसी तरह एडीजीपी वाई पूरण के जाने से उनका परिवार भी आहत है। संदीप के परिवार को एडीजीपी के परिवार के प्रति भी सहानुभूति है। एडीजीपी के परिवार की तरफ से एक 32 सदस्यीय कमेटी गठित है। सरकार से मांग है कि एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए। इसमें दोनों परिवारों के सदस्यों को शामिल किया जाए। दोनों परिवारों की संपति की जांच होनी चाहिए।

पेंट हाउस अग्निकांड-हाईटेक लॉक सिस्टम और रूम पैक होने से धुआं बाहर नहीं निकल पाया

इंदौर । इंदौर में उद्योगपति प्रवेश अग्रवाल की अपने ही पेंट हाउस में दम घुटने से मौत हो गई। वे अपनी बेटी को कमरे से बचाने गए थे, लेकिन खुद कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। जब पुलिस जवान पेंट हाउस में पहुंचे तो उन्हें हाईटेक लॉक खोलने में भी परेशानी आई,क्योंकि आग के कारण बिजली गुल हो गई थी। दरवाजे पर डोर कैमरे व फिंगरप्रिंट लॉक थे। जैसे-तैसे ताला तोड़कर प्रवेश को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पेंटा हाउस में कम खिड़कियां थी, इसलिए धुएं को निकले के पर्याप्त जगह नहीं मिली। इस कारण भी हादसे ने भयावह रुप ले लिया। दरअसल प्रवेश ने अपने आटोमोबाइल के शोरुम के ऊपर ही पेंट हाउस रहने के लिए बनवाया था। उसका इंटीरियर इस तरह किया गया था कि पेंट हाउस भी शोरुम का हिस्सा लगे। इसके लिए मोटे कांच का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। जो सेंट्रल एसी शोरुम के लिए था, उससे ही पेंट हाउस का भी जोड़ गया था। इस कारण ज्यादातर समय खिड़कियां बंद रहती थी। इस कारण आग लगते ही सभी कमरों में धुआं भर गया था। प्रवेश ने दीपावली के समय पांच दिन के लिए पूजा घर में अखंड ज्योत जलाई थी। आशंका है कि चूहों ने दीपक को गिरा दिया और आग लग गई। आग सबसे पहले पूजाघर में लगी। पेंट हाउस में फायर अलार्म सिस्टम नहीं थे। यदि होते तो प्रवेश और उनका परिवार समय रहते जाग जाता और हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं होती। कमरों में फोरेंसिक विशेषज्ञों को चूहे भी मृत मिले। विशेषज्ञों को शार्ट सर्किट के कारण आग लगने के सबूत नहीं मिले। कई बार आग लगने के कारण प्रभावित घबरा जाते है और अपनी जान गंवा बैठते है, लेकिन यदि सुझबूझ से काम लिया जाए तो हादसे से बचा जा सकता है। आग लगने धुएं के स्तर से नीचे झुककर या रेंगकर बाहर निकले। इससे ज्यादा धुआं सांसों में नहीं भर पाएगा। कोशिश करे कि आग लगने पर बचने के लिए छत पर जाए, वहां खुला हिस्सा रहता है और बचाव भी जल्दी होने की संभावना रहती है। यदि आप कमरे में फंसे है तो धुएं से बचने के लिए खिड़की के कांच फोड़ दे और दौड़ते हुए न निकले। इससे सांसों में धुएं की मात्रा ज्यादा जाती है।

थप्पड़बाज एसडीएमः पत्नी नहीं तो कौन थी कार में बैठी महिला, जिसने की छेड़छाड़ की

भीलवाड़ा । थप्पड़बाज एसडीएम का विवादों से पुराना नाता रहा है। पंप कर्मियों से मारपीट करने वाले एसडीएम के सस्पेंशन के बाद अब मामले में एक और नया पेंच निकलकर सामने आया है। घटना के बाद पंप कर्मियों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला असल में एसडीएम की पत्नी है ही नहीं।

दरअसल घटना के समय एसडीएम छोटूलाल शर्मा के साथ गाड़ी में बैठी महिला ने खुद को एसडीएम छोटूलाल की पत्नी बताते हुए थाने में पंप कर्मियों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि घटना के समय एसडीएम छोटूलाल शर्मा के साथ गाड़ी में एक महिला दीपिका व्यास मौजूद थीं। मारपीट के बाद महिला ने खुद को एसडीएम की पत्नी बताकर थाने में शिकायत दी थी कि पेट्रोल पंप कर्मियों उसे गलत तरीके से घूरा, आंख मारी और गंदे कमेंट किए, जिससे उसके पति को एसडीएम छोटूलाल को गुस्सा आ गया। जब उन्होंने पंप कर्मचारियों का विरोध किया तो मारपीट शुरू हो गई। इसके कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंप के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दीपिका व्यास एसडीएम की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी नहीं हैं। एसडीएम छोटूलाल की शादी 2008 में पूनम शर्मा नाम की महिला से हुई है।

जानकारी में पता चला है कि कथित तौर पर पूनम घर से निकाले जाने के बाद अपने बच्चों के साथ अलग रहकर संघर्ष कर रही हैं। जानकारी के अनुसार पूनम ने अपने पति के खिलाफ तलाक के पेपर में जाली सिग्नेचर करने की शिकायत भी दर्ज करवा चुकी हैं और जोधपुर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है। एसडीएम छोटूलाल शर्मा को उनके खराब रवैये के चलते एक बार नहीं तीन बार पद से हटाया जा चुका है। पहली बार उन्हें पंचायत समिति विकास अधिकारी के साथ झगड़े के आरोप लगने के बाद कार्रवाई करते हुए पद से हटाया गया था। दूसरी बार माइनिंग गतिविधियों से जुड़ी गड़बड़ियों के उनकी संलिप्तता के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके बाद एसडीएम टोंक रहते हुए उन पर अपने चपरासी पर हमला करने का आरोप लगा था। ये मामला रिश्वत से जुड़ा बताया जाता है। इसके कांड के बाद भी एसडीएम पर कार्रवाई हुई थी। घटना के अनुसार 21 अक्तूबर को भीलवाड़ा के रायला थाना इलाके में अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार दोपहर सबसे छोटूलाल शर्मा अपनी कार लेकर आए। तभी उनके पीछे-पीछे एक और कार पंप में आई। दोनों ही कारें सीएनजी डलवाने पहुंची थीं। इस दौरान पंप का कर्मचारी पीछे आई गाड़ी में सीएनजी गैस भरने लगा। इस बात पर तमतमाए एसडीएम ने पेट्रोल पंपकर्मी को थप्पड़ मार दिया और कहा कि पहले मैं आया तो पीछे वाली कार में गैस क्यों भरी। इसके बाद पंपकर्मी ने भी एसडीएम को चांटा जड़ दिया था।

इसके बाद मामला बढ़ता चला गया। ये सारा मामला कैमरे में कैद हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने एसडीएम से मारपीट के मामले में तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। अब एसडीएम के खिलाफ एक्शन लिया गया है।

कांग्रेस नेता उदित राज का दावा- घर से बेदखल कर रही सरकार, सामान बाहर फेंका

नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज ने एक्स पोस्ट के जरिए बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय के अधिकारी उनके आवास पर आए और उनके घर का सामान बाहर फेंका गया. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उदित राज ने जानकारी देते हुए लिखा है, मेरा सी1/38, पंडारा पार्क, नई दिल्ली-3 स्थित घर मेरी पत्नी सीमा राज के नाम पर आवंटित है. अधिकारियों का कहना है कि वे कल सुबह हमें यहां से बेदखल कर देंगे. मेरी पत्नी रिटायर्ड है और हमारा यहां ज्यादा समय तक रहने का कोई इरादा नहीं है. इसलिए हम एक निजी आवास की तलाश में हैं. उदित राज ने बताया कि वह आवास पर कुछ समय ज्यादा रुकने को मजबूर थे क्योंकि उनके ससुर लंबी बीमारी से जंग लड़ रहे थे और उनका निधन हो गया. हालांकि उदित राज ने खुद बताया कि वे नवंबर के अंत तक अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस आवास का किराया वैसे भी बहुत ज्यादा है और वह यहां मजबूरी में ही रह रहे हैं. पोस्ट में उदित राज ने लिखा, आज आए अधिकारियों ने हमें मंत्रालय में निदेशक/संयुक्त सचिव से बात करने की सलाह दी और हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. मेरी पत्नी ने मंत्रालय को हमारे प्रवास को कुछ समय के लिए बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। वह पटियाला हाउस कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में गई हैं, जिन्होंने उनकी अपील स्वीकार कर ली है और निदेशालय को नोटिस जारी कर दिया है और मामला 28.10.25 को सूचीबद्ध है. ऐसा लगता है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद, संपदा निदेशालय जानबूझकर छुट्टियों के दौरान जबरन बेदखली का सहारा ले रहा है, ताकि हमें कोई राहत न मिल सके. कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मुद्दे को जातिवाद से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो कृपापात्र हैं, लेकिन बेतुके बहाने बनाकर आलीशान बंगलों में रह रहे हैं. मैंने संबंधित मंत्री मनोहर लाल खट्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. अधिकारियों की चुनिंदा कार्रवाई और एक विपक्षी नेता को निशाना बनाना, जो निचली जाति से ताल्लुक रखता है और दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ उनकी आवाज उठाता है, मौजूदा सरकार में उच्च जाति के वर्चस्व वाले वर्ग के नापाक इरादों को दर्शाता है. इस मामले में इतनी जल्दी क्या है? मैं तो जल्द ही घर खाली करने को तैयार हूं, लेकिन यही पैमाना उन तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा जो उससे भी बड़े घरों में रह रहे हैं?

प्रशांत किशोर का बड़ा दांव, गोपालगंज के निर्दलीय प्रत्याशी अनुप श्रीवास्तव को दिया समर्थन

पटना)। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को गोपालगंज में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। इस मौके पर अनूप श्रीवास्तव ने जन सुराज में औपचारिक रूप से शामिल होने की भी घोषणा की। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति में अब 'बूथ लूट नहीं बल्कि' उम्मीदवारों की लूट हो रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि,'अनूप जी ने वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई। पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ता को नजरअंदाज कर धनबल के आगे झुक गयी। ऐसे में जन सुराज ने विचार- विमर्श कर उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा कि जन सुराज अब अनूप श्रीवास्तव को अपना अधिकृत उम्मीदवार मानता है, भले ही चुनाव चिह्न अलग हो। एक और एक मिलकर ग्यारह होंगे। गोपालगंज की जनता और भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि यहां अनुप जी जीतें और भाजपा अपनी गलती से सबक सीखे। किशोर ने बताया कि जन सुराज के प्रत्याशी डॉ शशि शेखर सिन्हा को दबाव में नामांकन वापस लेना पड़ा, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक मारा गया। इस गलती को सुधारने के लिए हमने अनुप जी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। वहीं, अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि वे 1973 से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन इस बार टिकट देने में पार्टी ने अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि,'मैंने पार्टी से इस्तीफा देकर स्वतंत्र रूप से नामांकन किया है। जन सुराज के समर्थन से यह लड़ाई अब जनता की हो गयी है।'

आईटीबीपी 64वां स्थापना दिवस: अमित शाह-भजनलाल शर्मा ने जवानों को दी बधाई

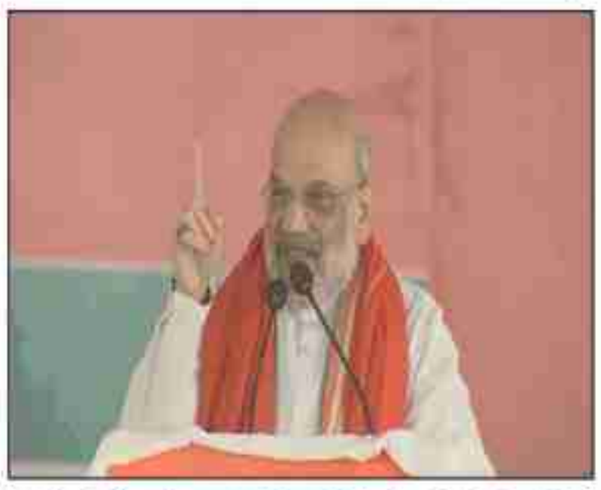

नई दिल्ली। आज भारत और तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का 64वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आईटीबीपी के 64वें स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी। शाह ने 'हिमवीरों' की कठिन पहाड़ी और कठोर जलवायु में देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी ने साहस और प्रतिबद्धता में शानदार मिसाल कायम की है और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी के जवानों के साहस और समर्पण की तारीफ की। साथ ही कहा कि उन्होंने शानदार मिसालें कायम की हैं और देश के लिए अपनी जान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आईटीबीपी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी आईटीबीपी के

जवानों की निष्ठा, अनुशासन और अदम्य साहस देश के लिए गर्व का विषय है। बता दें कि आईटीबीपी का गठन 24 अक्तूबर 1962 को हुआ था। वर्तमान में यह बल भारत-चीन सीमा की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करता है, जो लद्दाख के काराकोरम पास से अरुणाचल प्रदेश के जाचेप ला तक फैली हुई है। इसके अलावा, आईटीबीपी आंतरिक सुरक्षा और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियानों में भी सक्रिय है। आईटीबीपी के अधिकांश चौकियां 9,000 से 18,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां सर्दियों में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बल अपने जवानों को पर्वतारोहण, स्कीइंग और गहन युद्धक प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करता है।

इसके अलावा, आईटीबीपी हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य में 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में कार्य करता है। गौरतलब है कि पिछले छह दशकों में आईटीबीपी के जवानों ने अपने कर्तव्यों और राष्ट्र सेवा में कई बलिदान दिए हैं और देश की सेवा में हमेशा अग्रणी रहे हैं।

दिल्ली-भोपाल में दबोचे गए आतंकियों का निकला आईएसआईएस कनेक्शन

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआईएस से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को दिल्ली से तो दूसरे को मध्य प्रदेश के भोपाल से दबोचा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एक बार फिर से आतंकियों के खौफनाक इरादों को उजागर कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आतंकी दिल्ली को दहलाना चाहते थे। इन दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी आईएसआईएस से भी लिंक उजागर हुए हैं। अभी दिल्ली पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर ही दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे? बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये दोनों आतंकी दिल्ली में फिदायीन हमले की फिराक में थे लेकिन, पुलिस ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आतंकियों के नाम भी सामने आ गए हैं। बताया गया कि दोनों के नाम अदनान है। एक आतंकी को दिल्ली के सादिक नगर से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश के भोपाल से दबोचा गया है।

शीतकालीन पूजा स्थलों पर होंगे विशेष प्रबंध, तीन धामों के बाद अब बदरीनाथ के कपाट होंगे बंद

चमोली। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद 25 नवंबर को बदरीनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इसके बाद परंपरागत रूप से शीतकालीन पूजा स्थलों पर श्रद्धालु के लिए पूजा-अर्चना और दर्शनों के सरकार की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंत्री महाराज ने कहा कि चारधाम के शीतकालीन पूजा स्थलों के तहत भगवान केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ, बदरीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर (योगध्यान बद्री मंदिर), गंगोत्री स्थित मां गंगा की पूजा मुखबा में और यमुनोत्री स्थित मां यमुनोत्री की पूजा-अर्चना खरसाली में होगी। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण, चार धामों के देवता इन दिव्य स्थानों पर विराजमान रहते हैं।

इसलिए शीतकाल के दौरान श्रद्धालु इन स्थानों पर आकर सुगमता से पूजा-

अर्चना कर सकते हैं।महाराज ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा संपन्नता की ओर है। सरकार के सुनियोजित प्रयासों से यह यात्रा सफल और सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। इसके लिए मैं तीर्थयात्रियों, तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेष रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करता हूं। उनके अथक प्रयासों से मानसून सीजन में आए विभिन्न अवरोधों के बावजूद चारधाम यात्रा में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड का रुख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा देने के लिए हम सभी को प्रेरित किया है। इसलिए, सरकार ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए होटलों में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का भी निर्णय लिया है।मंत्री ने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा कर पुण्य लाभ अर्जित किया है।

अर्थव्यवस्था में हमारा बड़ा योगदान लेकिन..., प्रियांक खरगे ने केंद्र पर लगाया भेदभाव करने का आरोप

बंगलूरू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियांक खरगे ने कहा कि बिहार चुनाव का कर्नाटक के हिस्से के कर वितरण से कोई संबंध नहीं है, फिर भी राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

बंगलूरू। कर्नाटक के मंत्री और मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने कर वितरण को लेकर केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। बंगलूरू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियांक खरगे ने कहा कि बिहार चुनाव का कर्नाटक के हिस्से के कर वितरण से कोई संबंध नहीं है, फिर भी राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खरगे ने कहा कि हमारे वित्त मंत्री दो बार दिल्ली जाकर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में सबसे बड़ा योगदान देता है। हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब हैं और हमें हमारे काम के मुताबिक इनाम मिलना चाहिए, ताकि और रोजगार पैदा किए जा सकें। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि चाहे नारा अमृत काल हो, विकसित भारत या मेक इन इंडिया, असल में इन सबका केंद्र कर्नाटक ही है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, कोई एहसान नहीं। बता दें कि खरगे का यह बयान ऐसे समय आया है जब कर्नाटक सरकार लगातार केंद्र पर वित्तीय अन्याय का आरोप लगा रही है।

मुख्यमंत्री माझी ने ओडिशा में वेदांता विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर आश्वासन दिया: अनिल अग्रवाल

नई दिल्ली वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कंपनी का प्रस्तावित विश्वविद्यालय ओडिशा के अलावा कहीं और स्थापित नहीं किया जाएगा। अग्रवाल ने ओडिशा में समूह के अतिरिक्त एक लाख करोड़ रुपये के निवेश पर माझी के साथ चर्चा के बाद यह टिप्पणी की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''बैठक में वेदांता विश्वविद्यालय परियोजना पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि अगर कोई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है तो वह केवल ओडिशा में ही होना चाहिए। मैंने इसके लिए उनका धन्यवाद किया।''अप्रैल 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के बाद परियोजना के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

पीएम मोदी समस्तीपुर में बोले- जंगलराज को दूर रखेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार

पटना। पीएम मोदी ने एनडीए के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एनडीए का मतलब सुशासन, जनता की सेवा और विकास है। आपका उत्साह देखकर लगता है कि बिहार इस बार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। 2005 का अक्टूबर महीना ही था, जब बिहार ने जंगलराज से मुक्ति पाई थी। नीतीश कुमार ने नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था। लेकिन, 10 साल तक कांग्रेस और राजद की सरकार रही। यूपीए सरकार ने बिहार को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी। राजद वाले आपलोगों से दस साल तक बदला लेते रहे कि आपलोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? राजद वाले कांग्रेस को धमकाते थे कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की कोई बात मानी, बिहार में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमलोग आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। राजद वालों ने बिहार का विकास नहीं होने दिया। नीतीश कुमार ने दिन-रात बिहार के लिए काम करते रहे। बिहार को बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है, जहां विकास का कोई न हुआ हो। आप कहीं भी चले जाइए, वहां कोई न कोई विकास का काम चलता दिखाई देगा। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। कहा कि इन्होंने क्या किया है? यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यह

लोग हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। इन्होंने तो जननायक की उपाधि भी चोरी कर ली है। लेकिन, बिहार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों ने बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणापुंज मानती है। हमलोग गरीबों की सेवा में लगे हैं। आप बताइए गरीबों को पक्का घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, शौचालय, नल का जल और सम्मान का जीवन जीने के लिए हर तरह की सुविधा देना क्या उनकी सेवा नहीं है? एनडीए सरकार कर्पूरी ठाकुर की विचारधार को सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मैथिली भाषा में लोगों को नमन किया। भाषण के शुरुआत में ही उन्होंने फिर से एक बार एनडीए सरकार के नारे लगाए। कहा कि जंगलराज को बिहार दूर रखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों के दौरान इतनी बड़ी तादात में आपका आना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आप सबका नमन करता हूं। इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं। कल से छठी मैया के महापर्व का भी शुभारंभ होने जा रहा है।

इस बार आपके मूड ने यह पक्का कर दिया है कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, तब भी आएगी एनडीए सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार के लोग परेशान थे। शाम में निकलने से डरते थे। लालू परिवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया।

लालू पर तंज कसते हुए कहा कि अपने

महंत राजूदास का विवादित बयान

लखनऊ अकबरपुर के बनगांव रोड स्थित छित्तूनी गांव में रामलीला का उद्घाटन करने पहुंचे हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने अकबरपुर के सपा विधायक रामअचल राजभर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बाद सनातन पर टिप्पणी करना दुर्भाग्य की बात है। सनातन की परंपरा इतनी विशाल होने के बावजूद हमने किसी का अपमान नहीं किया। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को जूता लेकर ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला मनुष्य नहीं हो सकता है। रामचरितमानस का एक-एक पात्र अकल्पनीय है। राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर नीले ड्रम में भर दिया। एक तरफ वो है जो पति को वनवास हुआ तो खुद भी चली गई और दूसरी तरफ ऐसी घटना है। रामायण और रामचरितमानस के अध्ययन से समाज की अनेकों कुरीतियां खत्म हो सकती हैं। उन्होंने राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके जिले में कुछ राक्षस हैं उन्हें स्वीकार मत करो जूता लेकर उनका स्वागत करो क्योंकि इससे ही धर्म बचेगा।

कुरनूल बस हादसा: आग में जिंदा जले 20 यात्री

दोपहिया वाहन की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई जिसने देखते ही देखते पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया

बंगलूरू। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर के निकट एक निजी बस में दोपहिया वाहन से टक्कर के बाद आग लग गई, जिससे इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में बाइक सवार एक व्यक्ति भी शामिल है। हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, बंगलूरू से हैदराबाद जा रही बस में हादसे के दौरान करीब 41 लोग सवार थे। इसमें कहा गया है कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे आ गयी और इसके ईंधन टैंक का ढक्कन खुल गया जिससे आग लग गई। कुरनूल के जिला कलेक्टर डॉ ए सिरी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, यह दुर्घटना सुबह 3 से 3:10 बजे के बीच हुई जब बस एक बाइक से टकरा गई, जिससे ईंधन रिसाव हुआ और आग लग गई। 41 यात्रियों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी 20 में से 11 के शवों की अब तक पहचान हो पाई है। बाकी की पहचान के प्रयास जारी हैं। कुरनूल संभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक कोया प्रवीण ने बताया, 19 यात्री, दो बच्चे और दो चालक इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस का दरवाजा जाम हो गया और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को हैदराबाद से बंगलूरू जा रही निजी बस के यात्रियों के परिवारों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मदद के लिए उनके

अधिकारियों एम श्रीरामचंद्र (मोबाइल 9912919545) और ई चिट्टीबाबू (मोबाइल 9440854433) से संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के निर्देश के बाद यह हेल्पलाइन शुरू की गई। उन्होंने सरकार के मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव और पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी से बात की। मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारी एस हरीश और पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कुरनूल जिले के गडवाल जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दुर्घटनास्थल पर पहुंचने और राहत कार्यों का समन्वय करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में एक बस में आग लगने के कारण लोगों की हुयी मौत पर शोक प्रकट किया और इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। राष्ट्रपति ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक दुखद बस अग्निकांड में हुई मौतों की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिये प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुरनूल सड़क हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी संदेश के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, %आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुई दुर्घटना में जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे के बाद शोक जताते हुए कहा, कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुर गांव के पास हुई भीषण बस आग दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। हादसे के बाद गहरी नींद में सो रहे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

जबकि कई लोगों के आग में फंसने की भी खबर सामने आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को कुरनूल जनरल अस्पताल ले जाया गया। पूरी बस पूरी तरह जल गई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर यात्री हैदराबाद शहर के थे। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर फरार हो गए।